आदिवासियों का राजस्थान के विकास में अतुलनीय योगदान है- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने जन जातीय गौरव दिवस पर बेणेश्वर धाम में लाभार्थियों को टेबलेट, चैक व स्कूटी बांटी

डूंगरपुर/जयपुर, 16 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनजातीय समाज अपनी समृद्ध परंपरा, विशिष्ट संस्कृति तथा प्रकृति के साथ गहरे संबंध के लिए प्रसिद्ध है। इस समाज ने ऐसे वीर सपूत दिए हैं, जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश-प्रदेश का विकास इनकी

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आदिवासी बाहुल्य जिलों के ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों, त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीतामाता अभयारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर व मातृ कुण्डिया आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रूपए से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा।**

सक्रिय भागीदारी से ही संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी के तहत, राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में यह दिन आदिवासियों को समर्पित है। आदिवासियों ने राजस्थान की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बालिकाओं को स्कूटी व बैग वितरित किये।

इस विकास यात्रा में अतुलनीय योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री सोमवार को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेणेश्वर धाम की ऐतिहासिक भूमि आदिवासी आस्था का सबसे बड़ा केन्द्र है। राज्य सरकार द्वारा बेणेश्वर धाम के सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया जाएगा और इस संबंध में डीपीआर भी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनजाति समाज के खिलाड़ियों ने एशियन लेक्रोस गेम्स, राष्ट्रीय लेक्रोस चैंपियनशिप सहित, विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी बहुल जिलों के ऐतिहासिक, धार्मिक स्थलों, त्रिपुर सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीतामाता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृ कुण्डिया आदि को सम्मिलित करते हुए, 100 करोड़ रुपये से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट भी विकसित किया जाएगा।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आदिवासियों के तीर्थ बेणेश्वर धाम का सर्वांगीण विकास होगा।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ , सलूंबर एवं सिरोही जिले के 1 हजार 902 करोड़ रुपये के 326 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। शर्मा ने लखपति दीदी सम्मान योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली लखपति दीदियों को सांकेतिक चैक और टेबलेट सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परिसर में आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया एवं बालिकाओं को स्कूटी वितरित कीं।

प.बंगाल में भारी प्रशासनिक फेरबदल

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 16 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद, राज्य के शीर्ष नौकरशाहों को हटाने का आदेश दिया। इनमें नंदिनी चक्रवर्ती भी शामिल हैं, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार की मुख्य सचिव थीं। सभी अफसरों को चुनाव कार्यों से अलग रखा जाएगा।

राज्य में दो चरणों में मतदान होगा: 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। मतों की गिनती 4 मई को होगी।

आयोग ने 1993 बैच के आईएएस अधिकारी दुष्यंत नरियाला को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त

- **चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अफसरों को चुनाव ड्यूटी से हटाया।**

किया है। राज्य के पुलिस प्रमुख पीयूष पांडे की जगह सिद्ध नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया है। वहीं, कोलकाता पुलिस के आयुक्त सुप्रतिम सरकार की जगह अजय कुमार नंद को नियुक्ति दी गई है।

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को भी हटा दिया है और 1997 बैच की आईएएस अधिकारी संघमित्रा घोष को गृह और पहाड़ी मामलों की प्रधान सचिव नियुक्त करने का भी निर्देश दिया।

आयोग के सचिव सुजीत के. आर. मिश्रा के हस्ताक्षर वाले पत्र में कहा गया है, ''स्थानांतरित किए गए अधिकारियों को चुनाव समाप्त होने तक चुनाव से संबंधित किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।''

'होर्मुज़ से सुरक्षित रास्ता चाहते हो, तो जब्त किये तीन टैंकर छोड़ो'

ईरान ने अपने राजदूत के मार्फत सोमवार को भारत के सामने शर्त रखी

नई दिल्ली, 16 मार्च। अमेरिका और इज़रायल द्वारा हमला किए जाने के बाद से ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है। इससे पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि दुनिया का 20 फीसदी तेल इसी रास्ते से गुजरता है। भारत लगातार ईरान से सुरक्षित रास्ता देने की अपील कर रहा है, लेकिन अब खबर आई है कि ईरान ने इसके लिए एक शर्त रख दी है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, ईरान ने भारत से कहा है कि अगर उसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अपने जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता चाहिए, तो बदले में भारत को ईरान के जब्त किए गए 3 टैंकरों को छोड़ना पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ईरान के राजदूत ने इस संबंध में सोमवार को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात

- **गत 6 फरवरी को भारतीय कोस्टल अधिकारियों ने तीन तेल टैंकर जांच के लिये मुंबई तट के पास रोके थे। अमेरिका के प्रतिबंध के कारण ईरान से संबंधित ये टैंकर भारत ने जब्त कर लिये थे। तब से ही ईरान इन टैंकरों को छोड़ने की मांग कर रहा है।**

की। इस मीटिंग में ईरान ने भारत के सामने टैंकरों को छोड़ने के बदले में सुरक्षित रास्ता देने की पेशकश की है।

हालांकि इस रिपोर्ट पर न तो भारत और न ही ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। ज्ञातव्य है कि 6 फरवरी को भारतीय कोस्टल अधिकारियों ने तीन तेल टैंकरों को जब्त कर लिया था।

कथित तौर पर इनका संबंध ईरान से था और अमेरिका ने इन पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। ये जहाज, स्टेलर रूबी, एस्फाल्ट स्टार और अल जाफजिया थे, जिन्हें अवैध तेल व्यापार की गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में जांच के लिए मुंबई तट के पास रोका गया था। अब ईरान ने इन्हीं टैंकरों को छोड़ने की मांग की है।

इसके पहले ईरान की तरफ से कहा गया था कि भारत और ईरान पुराने दोस्त हैं। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दो जहाज भारत के लिए रवाना हो गए थे। इनमें से एक टैंकर भारत पहुंच चुका है, जबकि दूसरा मंगलवार को पहुंचेगा।

भाजपा ने बंगाल चुनावों के लिए 144 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की

ममता के खिलाफ लड़ेंगे शुभेन्दु, दिलीप घोष को भी मिला टिकट

कोलकाता, 16 मार्च। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी पहली उम्मीदवार सूची सोमवार को जारी कर दी है। पार्टी ने पहले चरण में 144 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। इस सूची में अधिकांश वर्तमान विधायकों पर फिर से भरोसा जताया गया है, जबकि कुछ सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है। खास बात ये है कि इस बार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, जिन्हें लंबे समय तक पार्टी ने दर किनार रखा था, उनकी पुरानी सीट खड़गपुर सदर से उम्मीदवार बनाया गया है।

भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष शुभेन्दु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों महत्वपूर्ण सीटों से उम्मीदवार बनाया है। इससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी इन हाई प्रोफाइल सीटों पर मजबूत राजनीतिक संदेश देना चाहती है। वहीं, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को एक बार फिर खड़गपुर

- **भाजपा ने कई मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया है। पार्टी ने अनुभव और संगठनात्मक संतुलन को तवज्जो देते हुए टिकट दिए हैं।**

सदर सीट से उम्मीदवार बनाया है। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता को रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है।

भाजपा ने कई मौजूदा विधायकों को पुन: मैदान में उतारा है। इनमें आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पाल, शालतोड़ा से चंदना बाउरी, डाबग्राम-फूलबाड़ी से शिखा चट्टोपाध्याय, तूफानगंज से मालती रावा राय, सिलीगुड़ी से शंकर घोष और भाटपाड़ा से पवन सिंह का नाम शामिल है।

इसके अलावा, कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। बालुरघाट से विधायक अशोक लाहिड़ी को टिकट नहीं दिया गया और उनकी जगह विद्युत राय को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह गोघाट से विश्वनाथ कारक की जगह प्रशांत डिगर, आरामबाग से मधुसूदन बाग की जगह, हेमंत बाग को उम्मीदवार बनाया गया है।

वाम मोर्चा ने प.बंगाल के लिये 192 प्रत्याशियों की घोषणा की

कोलकाता, 16 मार्च। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर वाम मोर्चा ने 192 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची सोमवार को जारी कर दी है। वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। सूची में माकपा, भारतीय कम्युनिस्ट

- **सूची में भाजपा, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, फारवर्ड ब्लाक, आरएसपी आदि सहयोगी दलों के नाम है।**

पार्टी, फारवर्ड ब्लॉक, आरएसपी सहित सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा दिखाई देता है।

माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने नाटाबाड़ी और तुफानगंज सीटों पर बाद में संशोधन की जानकारी भी दी। घोषित सूची से स्पष्ट है कि माकपा ने सबसे अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि फारवर्ड ब्लॉक, आरएसपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भी महत्वपूर्ण सीटें दी गई हैं।

उत्तर बंगाल की कई सीटों पर वाम मोर्चा ने अपने संगठन से जुड़े अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारा है। इनमें प्रमुख रूप से सिलिगुड़ी से शरदिंदु चक्रवर्ती, जलपाईगुड़ी से देबराज बर्मन, रायगंज से जीवनानंद सिंह, बालुरघाट से अर्णब चौधरी और गंगारामपुर से बिप्लब बर्मन शामिल हैं ।

ईरान ने इज़रायल पर दागी सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल

यह मिसाइल 2000 से 2500 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है

तेहरान, 16 मार्च। अमेरिका-इज़रायल और ईरान युद्ध का आज 17वां दिन है। ईरान ने रविवार को इस लड़ाई में पहली बार इज़रायल पर सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यह जानकारी ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की न्यूज एजेंसी तसनीम ने दी। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कल कहा कि ईरान ने न तो युद्धिवराम की मांग की है और न ही अमेरिका से बातचीत की पेशकश की है। जब तक जरूरत होगी, ईरान अपनी रक्षा करता रहेगा।

आईआरजीसी ने कहा कि सेजिल के माध्यम से इज़रायल के सैन्य और रक्षा सुविधा को निशाना बनाया गया है। यह मिसाइल 2000-2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। 28 फरवरी को अमेरिका-इज़रायल के

- **युद्ध का आज 17 वां दिन है और ईरान ने पहली बार इस मिसाइल का प्रयोग किया है**
- **ईरान के विदेश मंत्री ने अब्बास अराघची ने कहा ईरान ने युद्ध विराम की मांग नहीं की है।**

आक्रामक युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार है, जब सेजिल मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। वहीं, अमेरिकी न्यूज चैनल सीबीएस न्यूज को दिए साक्षात्कार में ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराघची ने कल कहा कि ईरान ने न तो युद्धिवराम की मांग की है और न ही अमेरिका से बातचीत की कोशिश की है। जब तक जरूरत होगी, ईरान खुद की रक्षा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान इस संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को यह स्वीकार करना होगा कि यह युद्ध न्यायसंगत नहीं है। जब तक वे स्वीकार नहीं करते, तब तक ईरान जवाब देता रहेगा। अराघची ने कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद देश की परमाणु सामग्री जमीन के नीचे दब गई है।

बेबस से ट्रंप ने नाटो देशों से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमेरिका के समर्थन के बिना अकेले रूस का सामना कर सकें? उस समय स्टार्मर के पास एक शिष्ट मुस्कान के अलावा कोई जवाब नहीं था।

एक अन्य यूरोपीय सहयोगी जर्मनी ने भी इसी तरह युद्ध में शामिल होने से इंकार कर दिया और कहा कि वह नाटो का युद्ध नहीं है। जर्मनी के चांसलर फ्रैडरिक मर्ज़ ने साफ कहा कि जर्मनी अमेरिका-इज़रायल के ईरान के साथ युद्ध में शामिल नहीं होगा।

इस तरह का जवाब मिलने पर ट्रंप गुस्से से भर गए और कहा कि नाटो गठबंधन का भविष्य ''बहुत खराब'' होने वाला है। देखा जाए तो, यह नाटो गठबंधन के उस स्वरूप का लगभग अंत ही है, जिस रूप में वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से काम करता रहा है।

कुछ समय पहले तक ट्रंम्प अक्सर यूरोपीय सहयोगियों को रूस के खतरे के सामने उनकी कमज़ोर रक्षा तैयारी के लिए नियमित रूप से डांटते रहते थे। अब, जब ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों के आवागमन को चुनौती दी है, तो डॉनल्ड ट्रम्प उसी संकरे समुद्री रास्ते से जहाजों को निकालने के लिए दूसरों से मदद मांग रहे हैं।

मानो उसी पुरानी बात का मीठा बदला लेने के लिए, अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों ने, होर्मुज़ से जहाजों के निकासी अभियान में शामिल होने की ट्रम्प की अपील को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। स्ट्रेट के दोनों छोर पर जहाजों की लंबी कतार लगी हुई है, जो पार जाने के अवसर का इंतजार कर रहे हैं। तथापि, इसके लिए ईरान की अनुमति आवश्यक होगी।

अपनी ओर से ईरान ने कहा है कि होर्मुज़ स्ट्रेट खुला हुआ है और कई जहाजों को बिना किसी बाधा के गुजरने दिया गया है। ईरान का कहना है कि वह केवल मार्ग को नियंत्रित कर रहा है, उसे बंद नहीं कर रहा। लेकिन ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि न तो अमेरिकी और न ही इज़रायली जहाजों को वहां से गुजरने दिया जाएगा।

अमेरिका के सामने इस सीधी चुनौती के बीच डॉनल्ड ट्रम्प ने पहले वादा किया था कि वह वाणिज्यिक जहाजों को अमेरिकी सुरक्षा घेरे के साथ भेजेंगे। लेकिन ईरानी मिसाइलों की विनाशकारी क्षमता और उनके हमलों को देखते हुए अमेरिकी नौसेना ने ऐसा करने से परहेज किया और उसने वहां से गुजरने की हिम्मत ही नहीं की।

ईरान ने भी यही कहा है कि अमेरिकी नौसेना में स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश करने का साहस नहीं था।

अब कई लोग ईरान युद्ध पर ट्रम्प के बयानों को गलत बयान बताकर उनपर सवाल उठा रहे हैं।

ट्रम्प पहले ही दावा कर चुके थे कि ईरान पर हमलों ने ईरान की पूरी नौसैनिक शक्ति को नष्ट कर दिया है और अमेरिका पहले ही ईरान पर जीत हासिल कर चुका है।

अब पूरे पश्चिमी मीडिया में खुले तौर पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि यदि ऐसा है, तो फिर ट्रम्प होर्मुज़ स्ट्रेट के गतिरोध को तोड़ने के लिए अन्य देशों से मदद क्यों मांग रहे हैं?

एलपीजी लेकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा जहाज शिवालिक

नई दिल्ली, 16 मार्च। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है।

खाड़ी देशों से एलपीजी लेकर भारतीय ध्वज वाला शिवालिक जहाज 45,000 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) लेकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट बंदरगाह पहुंच गया है। दूसरा जहाज नंदा देवी के भी जल्द आने के बाद देश में रसोई गैस की किल्लत कम होने के आसार हैं।

इससे पहले जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने संवाददाताओं को बताया कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटों में कोई घटना सामने नहीं आई है और हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं।

लोकसभा के 8 सांसदों का निलंबन वापस होगा

नई दिल्ली, 16 मार्च। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अध्यक्षता में सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में आठ निलंबित सांसदों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार, इन सांसदों का निलंबन मंगलवार को प्रश्नकाल के बाद औपचारिक रूप से वापस लिया जाएगा।

जिन सांसदों का निलंबन वापस लिया जाएगा, उनमें गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, बी. मणिकम टैगोर, डॉ. प्रशांत यदोराव पाडोले, चामला किरण कुमार रेड्डी और एस. वेंकटेशन शामिल हैं। इन सांसदों को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा लाए गए प्रस्ताव के आधार पर, तीन फरवरी से शुरू हुए सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया था।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में नेताओं ने संसद की गरिमा और स्थापित परंपराओं को बनाए रखने पर भी

- **सर्वदलीय बैठक में सहमति बनी कि मंगलवार को प्रश्नकाल के बाद यह मुद्दा उठाया जाएगा और निलंबन वापस लिया जाएगा**

सहमति जताई। इसके तहत यह तय किया गया कि कोई भी सदस्य सदन के वेल में दूसरी ओर नहीं जाएगा, कागज फाड़कर आसन की ओर नहीं फेंकेगा और न ही अधिकारियों की मेज पर चढ़ेगा। इसके अलावा, सभी सदस्य सदन की मर्यादा का पालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा न हों।

इस बीच लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को संसद परिसर में मर्यादा बनाए रखने के संबंध में एक बुलेटिन भी जारी किया है।

बिहार में महागठबंधन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे।

इसके बावजूद, महागठबंधन एक अजीब कारण से हार गया। कांग्रेस के तीन विधायक और आरजेडी का एक विधायक मतदान के लिए पहुंचे ही नहीं, जिससे एआईएमआईएम के पाँच और बीएसपी के एक विधायक के समर्थन का फायदा व्यर्थ हो गया।

कांग्रेस विधायक सुरेन्द्र प्रसाद कुशवाहा से पूरे दिन संपर्क नहीं हो सका तथा उनका मोबाइल फोन बंद रहा। एक अन्य कांग्रेस विधायक मनोज बिस्वास भी संपर्क से बाहर रहे। तीसरे कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने सुबह नेताओं को आश्वासन दिया था कि वे मतदान के लिए आएंगे, लेकिन वे भी नहीं पहुंचे।

आरजेडी के फैसल रहमान ने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी अनुपस्थिति का कारण उनकी मां के दिल्ली में चल रहे इलाज से जुड़ी व्यक्तिगत आपात स्थिति थी। इस तरह एनडीए के उम्मीदवारों ने सभी पाँच सीटें जीत लीं। जीतने वाले नेता हैं- भाजपा के नितिन नबीन और शिवेश कुमार राम, जदयू के नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर, तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के उपेन्द्र कुशवाहा।

खाड़ी वॉर पर भ्रामक पोस्ट करने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने और स्थिरता को कमजोर करने का प्रयास करती है।

यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी, ''वाम'' के अनुसार, बयान में कहा गया है कि जांच और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से पता चला कि आरोपियों को तीन समूहों में बाँटा जा सकता है, जिन्होंने अलग-अलग तरह के कृत्य किये। इनमें वर्तमान घटनाओं से जुड़े असली वीडियो क्लिप प्रकाशित करना, एआई की मदद से नकली वीडियो बनाना, और सैन्य कार्यवाही करने वाले देश (ईरान) के सैन्य हमलों का महिमामंडन करना शामिल था।

दस आरोपियों के पहले समूह, जिनमें पाँच भारतीय, एक पाकिस्तानी, एक नेपाली, दो फिलिपीनी और मिस्र का एक नागरिक शामिल हैं, ने यूएई के हवाई क्षेत्र में मिसाइलों के गुजरने या उन्हें रोके जाने से जुड़े असली वीडियो क्लिप प्रसारित किए। उन्होंने लोगों की भीड़ वाले वीडियो के साथ टिप्पणियाँ और ध्वनि प्रभाव भी जोड़े, जिससे सक्रिय हमले का आभास होता था और लोगों में घबराहट फैल सकती थी।

बयान में कहा गया कि ऐसे वीडियो देश की रक्षा क्षमताओं से जुड़ी जानकारी उजागर कर सकते थे और शत्रुतापूर्ण प्रचार को बढ़ावा दे सकते थे।

दूसरे समूह में सात लोग शामिल हैं-पाँच भारतीय, एक नेपाली और एक बांग्लादेशी। इन पर आरोप है कि उन्होंने एआई से बनाए गए नकली वीडियो या अन्य देशों की घटनाओं के फुटेज को यूएई का बताकर प्रसारित किया। इन क्लिपों में विस्फोट और मिसाइलों के कृत्रिम दृश्य दिखाए गए थे और उनमें राष्ट्रीय झंडे या तिथियाँ जोड़कर उन्हें विश्वसनीय दिखाने की कोशिश की गई।

तीसरे समूह में छह आरोपी हैं-पाँच भारतीय और एक पाकिस्तानी। इन पर आरोप है कि उन्होंने ''एक शत्रु देश (ईरान) और उसके राजनीतिक व सैन्य नेतृत्व का महिमामंडन करने वाली सामग्री'' पोस्ट की और उसके सैन्य कदमों को उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया।

बयान में कहा गया, ''इसमें उस देश के नेताओं की प्रशंसा, और उस दुष्प्रचार को बार-बार दोहराना शामिल है, जो राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है।''

इसके अलावा दो अन्य भारतीयों पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं। शनिवार को यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी ''वाम'' की रिपोर्ट में बताया गया था कि 10 आरोपियों से पूछताछ के बाद, उनका पब्लिक प्रॉसिक्यूशन हुआ तथा अदालत ने उन्हें हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अटॉर्नी जनरल अल शम्स ने कहा कि इन लोगों ने एआई से बनाए गए वीडियो फैलाए, जिनमें यूएई के प्रमुख स्थलों पर विस्फोट, हमले या बड़े पैमाने पर आग लगने जैसी झूठी घटनाएँ दिखाई गई थीं।

यूएई में ऐसे अपराधों के लिए कम से कम एक वर्ष की कैद और कम से कम 1,00,000 दिरहम का जुर्माना हो सकता है।

उन्होंने कहा, ''इन घटनाओं का इस्तेमाल जानबूझकर भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए किया गया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यवस्था और स्थिरता को नुकसान पहुँच सके।''

कुछ वीडियो में बच्चों की भावनाओं का भी अनुचित लाभ लेने की कोशिश की गई, और यह झूठा संकेत दिया गया कि देश की सुरक्षा को खतरा है। अन्य वीडियो में सैन्य ठिकानों के नष्ट होने या विदेशी घटनाओं को यूएई में घटित बताया गया। इसका उद्देश्य जन-भावना को गलत दिशा में ले जाना तथा चिन्ता और डर पैदा करना था।

संसद में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से हुई तकनीकी खराबी के कारण हुआ।

हालांकि, विस्तृत जांच जारी है कि बूम बैरियर तेज़ हवा की वजह से गिरा या उस समय परिसर में प्रवेश कर रही एक कार के एंट्री स्टिकर को पढ़ने में असमर्थ होने के कारण ऐसा हुआ।

पास में तैनात क्यूआरटी को तुरंत सक्रिय किया गया, लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि सुरक्षा अलार्म तकनीकी खराबी के कारण था, तो टीम वापस अपने स्थान पर लौट गई।

खार्ग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

छोटा और बंजर- सा द्वीप है, जहाँ से ईरान के अधिकांश कच्चे तेल का निर्यात होता है। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच यह विचार सामने आया है।

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यदि तेहरान की नाकेबंदी के कारण टैंकर फारस की खाड़ी में फँसे रहते हैं, तो ट्रम्प खार्ग द्वीप पर स्थित ईरान के महत्वपूर्ण तेल भंडार पर कब्ज़ा करने का आदेश दे सकते हैं।

यदि अमेरिका ऐसा कदम उठाता है, तो उसे जमीन पर अपनी सेना उतारनी होगी। इससे यह जोखिम बढ़ जाएगा कि ईरान, खाड़ी देशों में तेल प्रतिष्ठानों और पाइपलाइनों पर जवाबी हमले कर सकता है, खासकर सऊदी अरब में।

लेकिन पश्चिम एशिया में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी इज़रायल शायद अभी ईरान की जमीन पर अपनी सेना उतारने के मूड में नहीं है। भारत में इज़रायल के राजदूत रियुवेन अज़र ने दावा किया है कि न तो वॉशिंगटन और न ही यरूशलम ईरान पर जमीनी आक्रमण करने का इरादा रखते हैं।

'आर्थिक अनुदान सीधे ईरानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लागू करता है। इन प्रतिबंधों के कारण वैश्विक बैंक और भुगतान प्लेटफॉर्म ईरान से जुड़े मनी ट्रांसफर को प्रोसेस करने में बेहद सावधानी बरतते हैं। यहां तक कि वे देश भी, जो औपचारिक रूप से अमेरिकी प्रतिबंध लागू नहीं करते, अक्सर ऐसे लेन-देन से बचते हैं क्योंकि वे डॉलर-आधारित अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं।

एक्स पर एक पोस्ट में ईरानी दूतावास ने भारत में उन लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने युद्ध से प्रभावित नागरिकों को मानवीय सहायता देने में रुचि दिखाई। हालांकि, दूतावास ने कहा कि तकनीकी समस्याओं के कारण उसके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से दान प्राप्त करना कठिन हो गया है।

दूतावास ने लिखा, ''दूतावास के खाते में धन स्थानांतरित करने में बताई गई कुछ कठिनाइयों के कारण, हम अपने प्रिय भारतीय भाइयों और बहनों के निरंतर समर्थन के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं।''

अधिकारियों ने बताया कि वे इस समस्या को हल करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल दानदाताओं को गुगल पे जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उपयोग न करने की सलाह दी गई है। इसके बजाय दूतावास ने कहा कि नकद दान सीधे नई दिल्ली स्थित मिशन में किया जा सकता है।

इससे पहले दूतावास ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने खाते का विवरण साझा किया था, क्योंकि भारत के कई लोगों ने संघर्ष से प्रभावित ईरानी नागरिकों को सहायता भेजने की इच्छा जताई थी।

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क कड़े अनुपालन नियमों के तहत काम करते हैं, जिनका उद्देश्य प्रतिबंधों के उल्लंघन और अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकना है। ईरानी संस्थाओं से जुड़े लेन-देन अक्सर अतिरिक्त जांच या देरी का कारण बनते हैं, खासकर जब भू-राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ हो।

मौजूदा संघर्ष ने वित्तीय प्रणाली में ऐसी सावधानियों को और बढ़ा दिया है। बैंक और डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म आम तौर पर अमेरिकी वित्तीय प्रणाली से जुड़े वैश्विक क्लियरिंग नेटवर्क पर निर्भर करते हैं, इसलिए वे ऐसे किसी भी लेन-देन से बचना चाहते हैं जिसमें नियामकीय जांच का खतरा हो।

यह घटना भारत और ईरान के संबंधों की जटिलता को भी उजागर करती है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से सभ्यतागत और आर्थिक संबंध रहे हैं, विशेष रूप से ऊर्जा व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क के क्षेत्र में।

भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार भारत में 20 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं, जिनमें पश्चिम एशिया के बाहर की सबसे बड़ी शिया समुदायों में से एक शामिल है। ईरान, जहां शिया इस्लाम प्रमुख परंपरा है, ऐतिहासिक रूप से इन समुदायों के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध बनाए रखता आया है।

जैसे-जैसे पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज हो रहा है, भारत में दान प्राप्त करने में ईरानी दूतावास को हो रही कठिनाइयाँ यह दिखाती हैं कि आज के युद्ध केवल सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका असर वैश्विक वित्तीय प्रणाली तक फैल जाता है।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908